

श्रीगंगानगर (राज.)
जिला कलेक्टर (प्रशासन)

पनावली राजस्व लोक अदालत के सक्षम प्रस्तुत हुई। प्रस्तुत अधीन के सुसंगत तथ्य सक्षम में इस प्रकार है कि मूलराम पुत्र अमरराम के नाम से मौजा धमण्डिया बरानी तहसील पदमपुर के मुरब्बा नं 66 के 8 बीघा बरानी मूमि गैर खातेदारी दर्ज थी तथा उसने इस मूमि को ज़रिए मुख्तार आम नत्थासिंह पुत्र जंगीर सिंह ने अधीनारिह को विक्रय करने का सौदा ज़रिए डेकररानामा दिनांक 06.02.1995 को किया गया। तब से अब तक अधीनारिह उक्त मूमि पर कानून बला आ रहा है। मूलराम का देहान्त ही युका है उसका कोई वारिस नहीं है। रेसूडिट संख्या 2 ता 4 ने लालच बरा होकर अपने आप को वारिस होने का गलत प्रमाण पत्र जारी करवाकर ग्राम पंचायत से गलत वारिस प्रमाण पत्र बनवाकर पंचायत से इंतकाल संख्या 209 जारी करा लिया। इंतकाल संख्या 209

आदेश दिनांक : 26-06-15

- उपरिष्ठत : 1. श्री जसकरणसिंह सरा, श्री राजवीरसिंह अधिवक्तगण
अधीनारिहगण
2. श्री इन्द्रपाल सहारण, अधिवक्ता, रेसूडिट सं 2 से 4
3. राजकीय अधिवक्ता, रेसूडिट सं 1
4. रेसूडिट सं 5 की ओर से कोई हाजिर नहीं।

अधीन विरुद्ध आदेश 19-12-12 तहसीलदार, (राजस्व) पदमपुर
रेसूडिट सं

5. सरपंच, ग्राम पंचायत 69 एल एन पी तहसील पदमपुर।
मार्जवास तहसील पदमपुर
4. श्रीमती माही देवी पत्नी पूर्णराम कहिल पुत्री मूलराम नाथक निवासी
हिसामुकी तहसील धडसाना जिला श्रीगंगानगर।
3. श्रीमती धागु पत्नी बीरबलराम कहिल पुत्री मूलराम जालि नाथक निवासी
44 एन डी आर तहसील पीलीबंगा
2. श्रीमती सन्तोदेवी पत्नी मनकल कहिल पुत्री मूलराम नाथक निवासी बक
स्टेट आफ राजस्थान ज़रिये तहसीलदार राजस्व, पदमपुर।

बनाम

- अधीनारिह

1. बशीपराम पुत्र श्री कडा राम जालि नाथक निवासी रिडमलसर तहसील
पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

अधीन प्रकरण सं 67 / 12

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।
पीठाधीन अधिकासी : करणसिंह गाववाल, आर०ए०ए०ए०

जिला कलेक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राज.)



श्री गंगा नगर (राज.)
 जिला कलेक्टर (प्रशासन)

के खिलाफ अपील उपजिलाधीश राजख पदमपुर में पेश होने पर इंतकाल को निरस्त करने का मामला तहसीलदार पदमपुर को रिमाउड किया गया। तहसीलदार के समक्ष अपीलार्थ ने पेश होकर समस्त रिकॉर्ड पेश किया, मगर तहसीलदार ने फिर भी इंतकाल रेंसॉर्ट संख्या 2 ता 4 के हक में करने का आदेश पारित किया गया है। रेंसॉर्ट संख्या 2 ता 4 मुक्त मूलराम के न तो वारिसान है, ना ही कोई दरखावाही सर्बत ही पेश किया गया है, जब मामला विचारधीन है तो एतराज होने का केवल मात्र उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र लाकर पेश करने पर उसको ही मान्यता प्रदान की जा सकती है। अतः उनको वारिस मान कर अदालत मातहत ने मूल की है। बिना उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र के किसी प्रकार से वारिस घोषित नहीं किया जा सकता था, ना ही इंतकाल रेंसॉर्ट 2 ता 4 के हक में किया जा सकता था। मामला राजा में ग्राम पंचायत रिजमलसर लगती है तथा उसने वह प्रमाण पत्र जारी किया है कि मुक्त मूलराम का कोई वारिस नहीं है जबकि अदालत मातहत ने ग्राम पंचायत 69 एलएनपी को पक्षकार बनाया है दोनों ही पंचायत अलग अलग है एक और अदालत मातहत ने निर्णय की प्रति ग्राम पंचायत रिजमलसर को भेजने का अन्त में लिखा है, दूसरी ओर उसको पक्षकार नहीं बनाया गया है। अपीलार्थ ने पेश होकर एतराज पेश किए हैं। वारिसान का विवाद ही तो अदालत मातहत को साक्ष्य लेकर फंसना करना चाहिए था मगर रेंसॉर्ट 2 ता 4 जो कि मुक्त मूलराम वारिस नहीं है जमीन हलपना चाहते हैं उनको द्वारा कोई गवाह तक पेश नहीं किया ना ही अपने आप को मूलराम की पुत्री होने का कोई आवश्यक अन्य दरखावाही साक्ष्य ही पेश किया है, केवल मात्र वारिस प्रमाण पत्र को मान्यता नहीं दी जा सकती है। अपीलार्थ ने लिखित में 11.12.2012 को आपत्तियां पेश की है, मगर इसमें अंकित तथ्यों पर ना तो गौर किया ना विवेचन किया ना ही फाईजिंग दी है। अदालत मातहत ने ना तो कर्नली व विधिक प्रक्रिया को अपनाया है ना ही लैण्ड रिकॉर्ड कलस के आदेशानुसक प्रावधानों द्वारा 126 से 135 की पालना की है। कब्जा के बारे में जांच करवाना जरूरी था जो कि नहीं करवाई व कब्जा के अभाव में रेंसॉर्ट 2 ता 4 के नाम से कर्नल भी इंतकाल नहीं किया जा सकता था। मूलराम ने जब अपने जीवनकाल में ही मुख्यारनाम रजि. दिया व बेवान भूमि का किया तो यह स्पष्ट है कि किसी प्रकार से रेंसॉर्ट अथवा अन्य के नाम से इंतकाल नहीं किया जा सकता है। अपील स्वीकार कर आदेश जैरे अपील निरस्त करने का हुक्म फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर बाद रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर की गई। रेंसॉर्ट संख्या को जारि सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेंसॉर्ट तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलान्तस के विद्वान अधिवक्ता ने लिखित बहस के साथ मौखिक बहस में कहा है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलधीन आदेश पारित करने से पूर्व उन्हें विधिवत रूप से सुनवाई व साक्ष्य का अवसर नहीं दिया गया है। विवाहित भूमि अपीलार्थ ने जारि इंकरारनामा कय की हुई है। खरीद की दिनांक से विवाहित भूमि पर अपीलार्थ का कब्जा काबत है। अपीलार्थ को बिना सुने अधीनस्थान आदेश पारित किया गया है तथा कब्जे की जांच नहीं की गई है। कर्नली व विधिक प्रक्रिया को नहीं अपनाया गया है और ना ही लैण्ड रिकॉर्ड

श्री गंगा नगर (राज.)
 जिला कलेक्टर (प्रशासन)

(कर्मचारी विभाग)
 (अधीनस्थ कर्मचारी विभाग)
 (अधीनस्थ कर्मचारी विभाग)

कर्मचारी विभाग के आदेशात्मक प्रावधानों द्वारा 126 से 135 की पालना की है। विवादित मामलों में 66 के 2.150 पर अधीनस्थ कर्मचारी का कल्याण है जो जाति से नायक है। इस प्रकार निवेदन किया है कि अधीनस्थ कर्मचारी को जाकर अधीनस्थ आदेशात्मक कर्मचारी के रूप में नियमित किया है।

19-12-2012 अपास्त किया जाता है अधीनस्थ न्यायालय का अधीनस्थ आदेश दिनांक 19.12.2012 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रति किया जाता है कि सभी सम्बन्धित पक्षकारों को सूचना देई एवं साक्ष्य का समर्थित अवसर प्रदान कर देई, विवादित मामलों के कल्याण, अधीनस्थ कर्मचारी के पक्ष में करवाई गये बचान दस्तावेज को दृष्टिगत रखते हुए, लौट कर कल्याण की पालना कर देई पुनः नये सिरे से विधि सम्मत आदेश पारित करे। आदेश की प्रति के साथ रेकार्ड अधीनस्थ न्यायालय को वापिस भेजा जावे। उभय पक्षकार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 23.07.2015 को उपस्थित हो।

आज दिनांक 26-6-15 को भूरे द्वारा लिखया जाकर खर्च न्यायालय में सुनाया गया।



(अधीनस्थ कर्मचारी विभाग)
 (अधीनस्थ कर्मचारी विभाग)